इकाई-3

गरीबी

परिचय-

पिछले अध्याय में हमने मानव को उत्पादन का एक **'सक्रिय संसाधन'** के रूप में देखा। अब हम इस अध्याय में मानव संसाधन के स्वरूप पर प्रकाश डालें। यदि मनुष्य अपने जीवन निर्वाह करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता भी पूरा नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति एक खास **संवर्ग** में जाना जाता है और यह संवर्ग की पहचान ही उसकी **''गरीबी''** को दर्शाता है। बिहार अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा राज्य है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में बसती है जिसकी आमदनी बहुत ही कम है जिसके कारण वह अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है और गरीबी की मार उसे हमेशा सताती रहती है।

इस अध्याय में हम गरीबी रेखा, गरीबी उत्पन्न के कारण तथा इसके समाधान के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।

© BSTBPC Not to be Published

चित्र : 3.1

भूख और प्यास- रोटी की आस

गरीबी :
भारत में गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति का होना है, जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता है।

उपर्युक्त चित्र 3.1 में बिहार के गाँव के एक परिवार की गरीबी को दर्शाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि गरीबी के कारण लोग भूख और प्यास से तड़पते रोटी की आस में टकटकी लगाए हुए हैं।

उद्देश्य :

बच्चो! इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है कि हम तुम्हें गरीबी का अर्थ बतायें तथा इसके कारण, इसके निवारण, इसके प्रकार एवं इसके दुष्चक्र की चर्चा के साथ गरीबी के विभिन्न आयामों से परिचित करायें ।

इस अध्याय में बिहार राज्य के गरीबी के ऊपर भी विस्तृत प्रकाश आँकड़े सहित प्रस्तुत किया गया है। 'गरीबी उन्मूलन' हेतु केंद्र एवं राज्य स्तर पर किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर किया गया है। अतः गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। **सरकारी स्तरों** पर भी गरीबी दूर करने के विभिन्न प्रयासों का वर्णन करना भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। सिर्फ सरकार के ऊपर इसके निवारण को छोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है बल्कि गैर-सरकारी संस्था के द्वारा भी गरीबी कैसे मिटायी जाए? इसका भी प्रयास इस अध्याय के माध्यम से अवगत करना है।

अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे गरीब हैं। वे गाँवों के **भूमिहीन श्रमिक** भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी **झुग्गियों** में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण-स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले **बाल-श्रमिक** भी। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर गरीबी को देखते हैं। वास्तव में, देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है। इसका अर्थ यह है कि भारत में मोटे तौर पर 26 करोड़ लोग गरीबी में जीते हैं। साथ ही भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक गरीबों का **संकेद्रण** हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लम्बे अंतराल के बाद भी पूरे देश के लिए यह एक गंभीर चुनौती का विषय बना हुआ है।

© BSTBPC Not to be Published

गरीबी के दो विशिष्ट मामले

शहरी गरीबी

रामपुकार की कहानी

पैंतीस वर्षीय रामपुकार बिहार में पटना के निकट गेहूँ के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह छह सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के चार बच्चे शामिल हैं। उसे जहानाबाद के समीप गाँव में रह रहे अपने बूढ़े माता-पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामपुकार और निकट के शहर आरा में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं।

रामपुकार शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक कामचलाँऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी राधा देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। रामपुकार का परिवार किसी प्रकार दिन में दो बार दाल और चावल का अल्प-भोजन जुटा लेता है पर यह उन सबके लिए पर्याप्त नहीं होता । उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास दो जोड़े फटे-पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते । जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प-पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती ।

© BSTBPC Not to be Published

चित्र : 3.2

रामपुकार की कहानी

राजेन्द्र सिंह की कहानी

राजेन्द्र सिंह बिहार में नालन्दा के पास एक गाँव इसलामपुर का रहनेवाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है। इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे–मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 60 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन प्राय: खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। आठ सदस्यों का परिवार हमेशा दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। राजेन्द्र सिंह गाँव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएँ पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियाँ बीनने में ही गुजार देती है। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में दो वर्ष पूर्व मुत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे-धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है। राजेन्द्र सिंह वहाँ भी नहीं गया । उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा । नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है।

© BSTBPC
Not to be Published

चित्र : 3.3

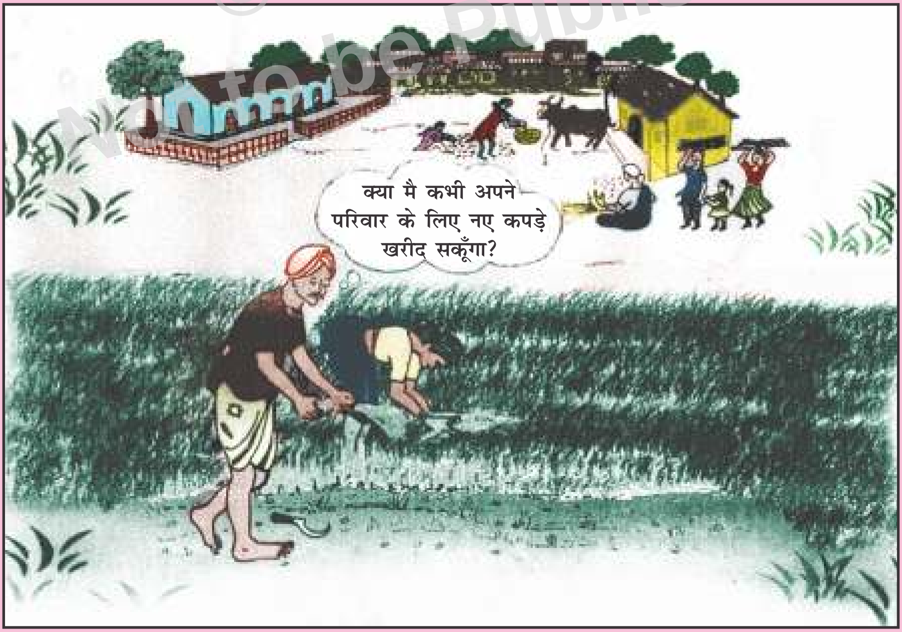

राजेन्द्र सिंह की कहानी

पीछे के दो विशिष्ट उदाहरण गरीबी के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि गरीबी का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी ईलाज नहीं करवा पाता। गरीबी का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। साथ ही यह नियमित रोजगार की कमी और न्यूनतम शालीनता स्तर के अभाव को भी बतलाता है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। गरीब लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिससे उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी-कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे-स्टेशनों इत्यादि लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति या आदमी गरीबी में जीना नहीं चाहता।

अपने करोड़ों लोगों को दयनीय गरीबी के चंगुल से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। **राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ के सबसे गरीब व्यक्तियों की हालत में सुधार होगा।**

© BSTBPC
Not to be Published

ग्रामीण गरीबी

राजेन्द्र सिंह की कहानी

राजेन्द्र सिंह बिहार में नालन्दा के पास एक गाँव इसलामपुर का रहनेवाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है। इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे–मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 60 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। आठ सदस्यों का परिवार हमेशा दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। राजेन्द्र सिंह गाँव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएँ पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियाँ बीनने में ही गुजार देती है। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में दो वर्ष पूर्व मुत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे–धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है। राजेन्द्र सिंह वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है।

© BSTBPC Not to be Published

चित्र : 3.3

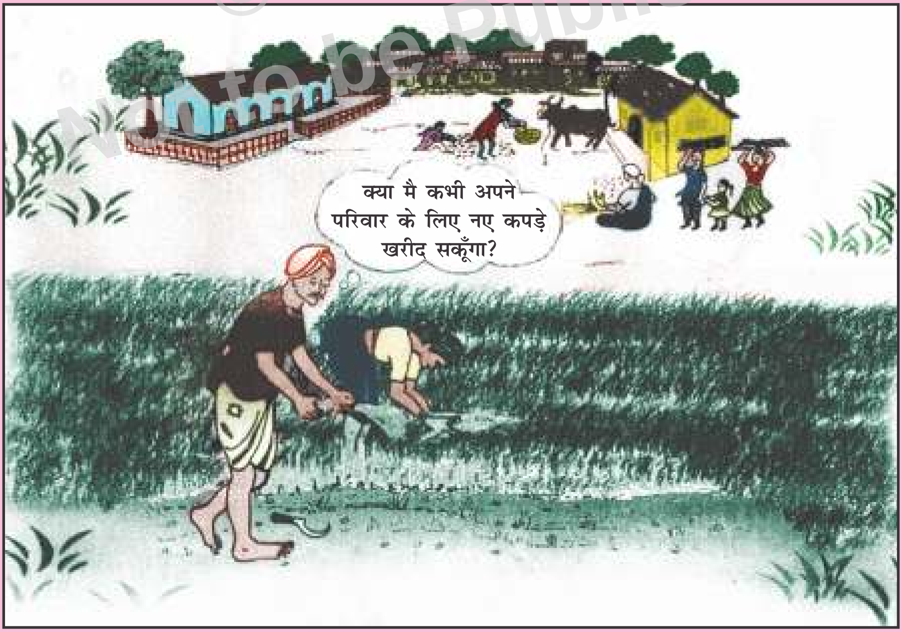

राजेन्द्र सिंह की कहानी

पीछे के दो विशिष्ट उदाहरण गरीबी के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि गरीबी का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता–पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी ईलाज नहीं करवा पाता। गरीबी का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। साथ ही यह नियमित रोजगार की कमी और न्यूनतम शालीनता स्तर के अभाव को भी बतलाता है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। गरीब लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिससे उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी–कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे–स्टेशनों इत्यादि लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति या आदमी गरीबी में जीना नहीं चाहता।

अपने करोड़ों लोगों को दयनीय गरीबी के चंगुल से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। **राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ के सबसे गरीब व्यक्तियों की हालत में सुधार होगा।**

© BSTBPC
Not to be Published

गरीबी का दुष्चक्र
(VICIOUS CIRCLE OF POVERTY)

गरीबी के दुष्चक्र से अभिप्राय ऐसी स्वचालित शक्ति की स्थिति से है, जिसमें कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं जो चक्रीय रूप में संबंधित होते हैं तथा जिसका परिणाम लगातार गरीबी तथा अल्पविकास होता है।

एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ''नर्क्स'' (Nurkse) गरीबी के दृश्य की व्याख्या गरीबी के दुष्चक्र के रूप में करते हैं –

''नर्क्स'' का कहना है कि गरीबी का दुष्चक्र बताता है कि चक्रीय रूप में जुड़ी शक्तियाँ एक–दूसरे के साथ इस प्रकार क्रिया तथा प्रतिक्रिया करती है कि गरीब देश सदैव गरीबी की अवस्था में ही रहता है।

गरीबी के दुष्चक्र कई प्रकार के होते हैं, उनमें से दो मुख्य इस प्रकार है – जिन्हें चित्र 'क' और चित्र 'ख' में दर्शाया गया है जो निम्नलिखित है।

चित्र : 3.4

क **ख**

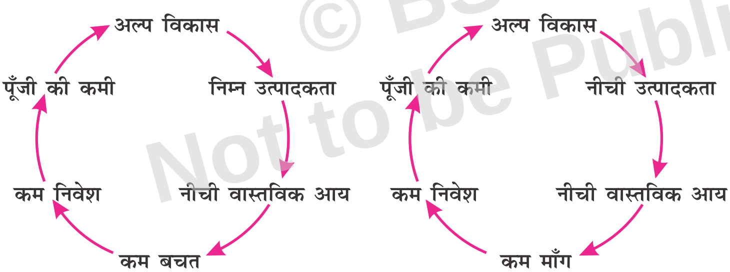

निर्धनता का दुष्चक्र या गरीबी का दुष्चक्र

गरीबी का दुष्चक्र: इससे अभिप्राय ऐसी स्वचालित शक्ति है, जिसमें कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं, जो चक्रीय रूप में संबंधित होते हैं तथा जिसका परिणाम लगातार गरीबी तथा अल्पविकास होता है।

© BSTBPC Not to be Published

चित्र 'क' दर्शाता है कि एक अल्पविकसित देश में कुल उत्पादन कम होता है जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक आय भी कम अथवा नीची होती है। इसी कारण लोग कम बचत करते हैं जिसका स्वत: अर्थ है **कम निवेश** तथा **कम पूँजी निर्माण।** कम पूँजी निवेश वाले देश सदैव अल्पविकसित रहते हैं तथा यह प्रक्रिया चक्रवत चलती रहती है।

चित्र 'ख' दर्शाता है कि एक अल्पविकसित देश की उत्पादकता नीची होती है, जिसका परिणाम कम वास्तविक आय होता है। जब लोगों की वास्तविक आय कम होती है, तो माँग में कमी आती है। इससे बाजार का आकार छोटा होने के कारण निवेश गिर जाता है, जिसके कारण कम पूँजी निर्माण होता है तथा यही प्रक्रिया फिर से आरंभ होती है।

सूचकांक द्वारा गरीबी की माप

चूँकि गरीबी के अनेक पहलू है, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं लेकिन अब गरीबी को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग-प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित गरीबी का विश्लेषण वर्तमान समय में अब बहुत सामान्य होता जा रहा है।

सामाजिक अपवर्जन :

इस अवधारणा के अनुसार गरीबी को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि गरीबों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहनेवाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे गरीबों के साथ रहना पड़ता है। मोटे तौर पर यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, जिनका उपभोग दूसरे (उनसे 'अधिक अच्छे') करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति-व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा गया है।

© BSTBPC Not to be Published

असुरक्षा :

गरीबी के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों (जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य) या व्यक्तियों (जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) के भावी वर्षों में गरीब होने या बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप, सुनामी, बाढ़) आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उन सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में, सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है।

गरीबी-रेखा

गरीबी पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतया गरीबी रेखा की अवधारणा होती है। गरीबी के आकलन की एक सर्वमान्य विधि आय तथा उपभोग स्तरों पर आधारित है। काल एवं स्थान के अनुसार गरीबी रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्त्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए **अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता की वस्तु मानी जाती है।**

> **गरीबी रेखा :**
>
> **योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है। MPCE के आधार पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रु० प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह निर्धारित किया है।**

भारत तथा बिहार में गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। कैलोरी का अर्थ भोजन से मिलने वाला सामान्य पोषक तत्व है। योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक श्रम करते हैं यानि शारीरिक कार्य अधिक करते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गयी है। अनाज आदि के रूप में कैलोरी आवश्यकता को खरीदने के लिए प्रतिव्यक्ति मौद्रिक व्यय तथा कीमतों में वृद्धि के आधार पर **मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय** (MPCE) के द्वारा वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रु० प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 454 रु० प्रतिमाह किया गया था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए अधिक राशि निश्चित की गई थी। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक रहती हैं। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, एक व्यक्ति के द्वारा खर्च किये जाने वाले उस राशि से है जिससे उसके आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ अर्थात् खाद्यान्न वस्तु एवं आवास प्राप्त होता है।

आकलन के वर्ष अर्थात् वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार गरीबी रेखा के नीचे होगा, यदि उसकी आय लगभग 1,640 रु० प्रतिमाह से कम है। इसी तरह के पाँच सदस्यों वाले परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए कम से कम 2,270 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होगी। गरीबी रेखा का आकलन

© BSTBPC Not to be Published

समय-समय पर (सामान्यतः हर पाँच वर्ष पर) प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात् नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एन. एस. एस. ओ) के द्वारा कराया जाता है, तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता या गरीबी रेखा के लिए एक मापदंड का प्रयोग करते हैं, जैसे—एक डॉलर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर ।

गरीबी के अनुमान :

भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हाल के वर्षों में कुछ कम हुई है। इसे निम्न तालिका के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

तालिका-3-1

	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत)			निर्धनों की संख्या (करोड़)		
वर्ष	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त योग
1973 – 74	56.4	49.0	54.9	26.1	6.0	32.1
1993 – 94	37.3	32.4	36.0	24.4	7.6	32.0
1999 – 00	27.1	23.6	26.8	19.3	6.7	26.0
2004 – 05	21.8	21.7	21.8	17.0	5.0	20.0

स्रोत :– आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत में गरीबी अनुपात वर्ष 1973 में लगभग 55 प्रतिशत थी जो वर्ष 1993 में घटकर 36 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2000 में गरीबी रेखा के नीचे के गरीबों का अनुपात और भी गिर कर 26 प्रतिशत पर आ गया । यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20 प्रतिशत से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दो दशकों (1973-93) में गिरा है, गरीब लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही। नवीनतम अनुमान में भारत में गरीबों की संख्या लगभग 20 करोड़ मानी जाती है।

© BSTBPC Not to be Published

असुरक्षित समूह

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह गरीबी के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार, आर्थिक समूहों में सबसे अधिक असुरक्षित समूह, ग्रामीण खेतिहर मजदूर परिवार और नगरीय अनियत मजदूर तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर परिवार हैं।

आरेख 3.1 : भारत में गरीबी 2000 सर्वाधिक असुरक्षित समूह

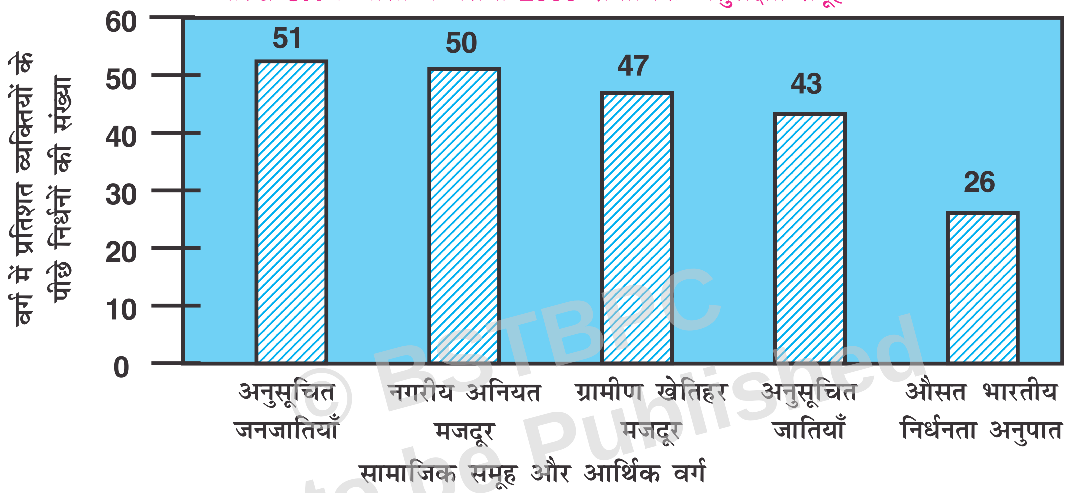

स्रोत : रिपोर्ट ऑन एंप्लायमेंट एंड अनएंप्लायमेंट अमौंग सोशल ग्रुप्स इन इंडिया नं० 469, 472 एन.एस.एस.ओ., मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

© BSTBPC Not to be Published

निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूहों में गरीब लोगों के प्रतिशत को दिखाता है। ऐसे गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 26 है। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 51 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनियत मजदूर गरीबी रेखा के नीचे हैं। लगभग 50 प्रतिशत भूमिहीन कृषक मजदूर और 43 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ भी गरीब हैं।

इन सामाजिक समूहों के अलावे परिवारों में भी आय की **असमानता** है। गरीब परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी सुव्यवस्थित परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित किया जा सकता है। इसलिए महिलाएँ, शिशु (खासकर बच्चियाँ) और वृद्ध गरीबों में भी गरीब होते हैं। इसे एक चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

गैर-सरकारी प्रयास :

गरीबी के निदान के रूप में कुछ गैर-सरकारी प्रयास भी किए जा रहें हैं जो निम्नलिखित हैं:-

1. स्वरोजगार :-सरकारी प्रयास के अतिरिक्त गैर-सरकारी प्रयास भी गरीबी दूर करने के लिए गाँवों एवं शहरों के स्तर पर काफी कारगार सिद्ध हुआ है। इसके लिए गरीब व्यक्ति सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंक की सहायता से खुद रोजगार करना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए व्यक्ति स्वयं रोजगार को चुनता है और अपनी इच्छानुसार काम कर आय अर्जित करता है तथा धीरे-धीरे बैंक से लिए गए कर्ज को चुकता करता जाता है। कर्ज समाप्ति के बाद व्यक्ति का वह रोजगार अपना हो जाता है और वह व्यक्ति स्वावलम्बी हो जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति के रहन-सहन में आय बढ़ने के कारण बदलाव आ जाता है।

2. सामूहिक खेती :-

कृषि में छोटे-छोटे कठिनाइयों को आसानी से दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाने लगा। भारतीय कृषि में मूलतः कुछ विसंगतियाँ हैं जैसे–खेतों का विखंडन, खेतों पर मेड़ों का होना, सिंचाई के साधन का अभाव होना, फसलों की सुरक्षा का अभाव इत्यादि। इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए सामूहिक खेती का उद्गम हुआ। फलस्वरूप गरीब कृषक तथा गरीब मजदूर की खेती में लगायी जाने वाली पूँजी की सुरक्षा की गारंटी भी सामूहिक खेती की ही देन है। यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और लोग एक-दूसरे के दुख व हानि आपस में बाँटते हैं जिसके कारण किसी खास पर हानि का बोझ नहीं पड़ता है और गरीब से गरीब भी अपने इस प्रयास से जीवनशैली में बदलाव लाते हैं।

चित्र : 3.7

एक साथ कई महिलाएँ धान की रोपनी करती हुई।

इस चित्र 3.7 में यह स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि खेतों में एक साथ काफी महिलाएँ सामूहिक रूप से खेती कर रही हैं जो आपस में काम के अलावा अपने सुख-दुख को भी बाँटती हैं।

© BSTBPC Not to be Published

बिहार में गरीबी अन्य राज्यों की तुलना में

वित्तमंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2001–02 ने भारत के कुछ राज्यों में गरीबी के अनुपात का वर्णन किया है जिसे निम्न आरेख से दिखाया गया है:–

आरेख 3.2 भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात

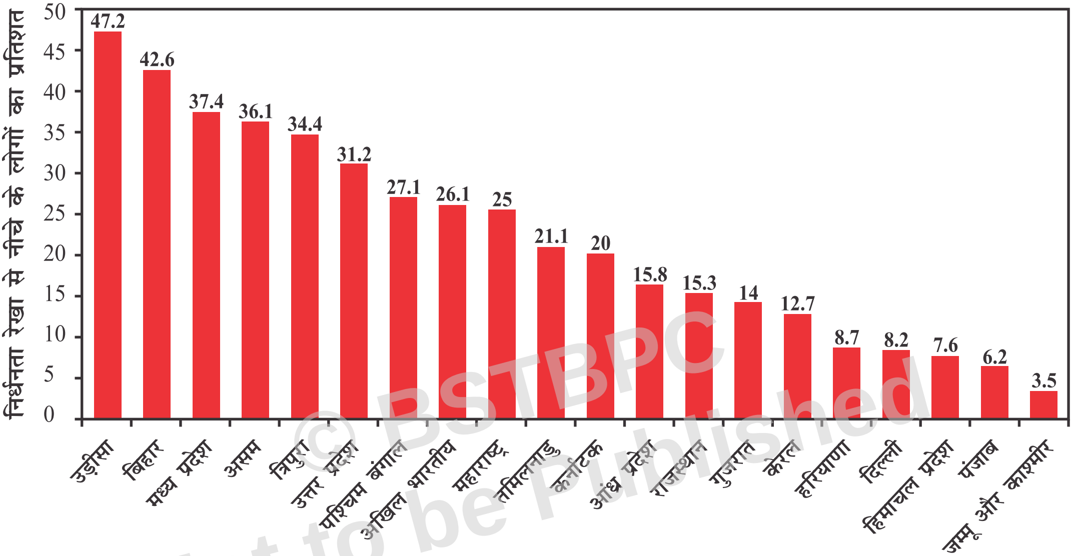

© BSTBPC
Not to be Published

स्त्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2001–02 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

इसके अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत बिहार में 42.6 प्रतिशत है जबकि जम्मू और कश्मीर जैसे राज्य में यह प्रतिशत मात्र 3.5 है। **बिहार भारत के गरीबी के आधार पर दूसरा राज्य है जबकि उड़ीसा प्रथम जहाँ कि गरीबी अनुपात 47.2 प्रतिशत है।** इस प्रकार देखते हैं कि बिहार के साथ अन्य राज्यों में भी गरीब लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय गरीबी में सुदीर्घकालिक कमी हुई है इसके कारण गरीबी कम करने में सफलता की दर बिहार के साथ–साथ विभिन्न राज्यों में अलग–अलग है।

गरीबी के कारण

भारत में गरीबी के अनेक कारण हैं जिसमें निम्न प्रमुख है:-

गरीबी के मुख्य कारण:-

- जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि
- कृषि का पिछड़ापन
- पूँजी का अभाव
- प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव
- औद्योगीकरण का अभाव
- आय तथा धन की विषमता
- बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी
- विदेशी शासन
- प्रतिकूल सामाजिक वातावरण
- यातायात के साधनों की कमी

1. जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि–भारत की गरीबी का मुख्य कारण देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश में पहले तो जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक थी जो अब लगभग 1.7% पर आ गई है। फिर भी यह विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। इसके चलते लोगों का जीवन-स्तर गिर रहा है तथा देश की गरीबी बढ़ रही है।

2. कृषि का पिछड़ापन–भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 64% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन उत्तम खाद, बेहतर किस्म के बीज तथा सिंचाई की सुविधा के अभाव में वह पिछड़ी हुई अवस्था में है।

3. पूँजी का अभाव–पूँजी की कमी देश में गरीबी को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है क्योंकि गरीबी के कारण लोगों में बचत की क्षमता कम होती है। बचत के अभाव में अपेक्षित विनियोग नहीं हो पाता। पूँजी निर्माण की गति धीमी रहती है जिसके कारण आर्थिक क्रियाओं का विकास तथा विस्तार नहीं हो पाता।

4. प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव–भारत में प्राकृतिक साधनों एवं मानवीय साधनों की प्रचुरता है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 50% प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का आर्थिक विकास के लिए प्रयोग नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में भारत के लोगों का गरीब होना स्वाभाविक है।

5. औद्योगीकरण का अभाव–हमारे देश में उद्योगों का विकास एवं विस्तार तेजी से नहीं हुआ है जिसके कारण कृषि क्षेत्र से जनसंख्या का हस्तांतरण उद्योगों में नहीं हुआ है। इसके कारण लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। आय के बेहतर स्रोत के अभाव में तथा बेकारों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लोगों में गरीबी वर्तमान है।

6. आय तथा धन की विषमता–हमारे देश में आय एवं धन के वितरण में काफी

© BSTBPC Not to be Published

विषमता है। देश की आय एवं सम्पत्ति का अधिकांश भाग कुछ सीमित व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित है। इसके कारण एक ओर धनी और धनी बनते हैं जबकि गरीब और अधिक गरीब, जिसके कारण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है।

7. बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी–भारत औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश है। उद्योग धंधों के अविकसित होने के कारण यहाँ व्यापक रूप में बेरोजगारी पायी जाती है। काम के इच्छुक लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। अतः बड़े पैमाने पर गरीबी मौजूद है जो गरीबी की समस्या का एक मुख्य कारण है।

8. विदेशी शासन–हमारे देश पर ब्रिटिश शासकों ने काफी लंबे समय तक शासन किया जिसने हमेशा शोषण की नीति का अनुसरण किया । ब्रिटिश शासकों की नीति ऐसी थी जो उनके आर्थिक नीति के अनुरूप थी तथा भारत के हितों के विरुद्ध थी। उनकी इस नीति के कारण भारत के विकसित कुटीर उद्योगों का पतन हुआ और लाखों लोग गरीबी के शिकार हो गए।

© BSTBPC Not to be Published

9. प्रतिकूल सामाजिक वातावरण–भारत में शिक्षा का घोर ही अभाव है। अधिकांश भारतीय अशिक्षित एवं रूढ़िवादी होते हैं जिसके कारण वे अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना नहीं चाहते। इसके कारण भी देश में गरीबी विद्यमान है।

10. यातायात के साधनों की कमी–भारत में यातायात के साधनों की कमी है, इसके चलते हमारे आर्थिक विकास की गति मंद है। देश के विकास के लिए इन साधनों का विकास भी आवश्यक है।

गरीबी उन्मूलन के उपाय

हमलोगों ने देखा है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी में निवास करती है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी का भार दृष्टिगोचर होता है। गरीबी आज भी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। गरीबी उन्मूलन के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं जिनमें निम्न प्रमुख हैं:–

1. प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग–चूँकि भारत में प्राकृतिक साधनों की

कमी नहीं है। अभी तक उनका पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे हैं। कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है लेकिन भारतीय गरीब हैं जिसका अर्थ यह है कि भारत में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है किन्तु यहाँ के निवासी गरीबी का जीवन व्यतित करते हैं। अतः गरीबी दूर करने के लिए देश के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का समुचित उपयोग होना चाहिए।

2. जनसंख्या पर नियंत्रण–देश की जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण करके ही गरीबी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। शिक्षा के प्रचार तथा परिवार नियोजन के लाभ की जानकारी देते हुए जनसंख्या नियंत्रण को जन आंदोलन का रूप देना जरूरी है।

गरीबी उन्मूलन के निम्न उपाय:-

1. **प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग**
2. **जनसंख्या पर नियंत्रण**
3. **कृषि उत्पादन में वृद्धि**
4. **देश का औद्योगीकरण**
5. **पूँजी की व्यवस्था**
6. **यातायात के साधनों का विकास**
7. **आय तथा धन का समान वितरण**
8. **रोजगार के अधिक अवसर**
9. **लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास**
10. **निवेश में वृद्धि**

3. कृषि उत्पादन में वृद्धि–हमारा देश मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग जनसंख्या का 2/3 भाग (दो-तिहाई) कृषि पर आश्रित है। कृषि को आधुनिक बनाकर उत्तम खाद, बीज एवं उर्वरकों का प्रयोग तथा आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। कृषि का तीव्र विकास करके गरीबी को दूर किया जा सकता है।

4. देश का औद्योगीकरण–गरीबी की समस्या के समाधान के लिए देश का औद्योगीकरण भी अनिवार्य है। इससे कृषि पर से जनसंख्या का बोझ कम होगा। लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनकी प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होगी।

5. पूँजी की व्यवस्था–चूँकि कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त पूँजी आवश्यक है। भारत में बचत एवं पूँजी निर्माण की दर बहुत कम है। पूँजी की समुचित व्यवस्था करने के लिए देश में पूँजी को भी आकृष्ट करना होगा।

6. यातायात के साधनों का विकास–यातायात के साधनों के विकास द्वारा देश में विकास की गति को तेज किया जा सकता है। यातायात के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है जो गरीबी दूर करने में सहयोग देती है।

7. आय तथा धन का समान वितरण–देश में आय तथा धन का समान वितरण करने की आवश्यकता है। धनी लोगों पर प्रगतिशील कर लगाने की जरूरत है तथा उनकी आय पर सीमा-निर्धारण होना चाहिए। प्रगतिशील कर का अर्थ आय बढ़ने के साथ करों की दरों में बढ़ोत्तरी होना है। निर्धन वर्ग के लोगों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए धनी वर्ग

© BSTBPC Not to be Published

के लोगों से साधन जुटाने की आवश्यकता है। इन सुविधाओं के विकास द्वारा उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी तथा गरीबी दूर करने के अवसर मिलेंगे।

8. रोजगार के अधिक अवसर–सरकार को छोटे तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करनी चाहिए। रोजगार में वृद्धि करने के लिए अधिक सार्वजनिक कार्य को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

9. लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास–देश में मौजूद लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी और यह गरीबी को कम करने में मदद करेगी।

10. निवेश में वृद्धि–कुछ राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश इत्यादि पिछड़े हुए राज्य हैं। इन राज्यों में गरीब लोगों की संख्या काफी हैं। अतः गरीबी दूर करने के लिए इन राज्यों में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है।

सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास

सरकारी प्रयास

- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम
- राज्य रोजगार गारंटी कोष
- मध्याह्न भोजन योजना
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
- समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- जवाहर रोजगार योजना
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
- स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना

गैर सरकारी प्रयास :-

- स्वरोजगार
- सामूहिक खेती
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम
- स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)

© BSTBPC Not to be Published

प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवीं योजना में गरीबी दूर करने संबंधी विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा देश एवं स्थानीय स्तर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जो गरीबी दूर करने में काफी मददगार साबित हुए।

गरीबी दूर करने के लिए किये गये सरकारी प्रयास निम्न हैं :–

1. राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम:– यह भारत सरकार के द्वारा 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिले में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए हैं, जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने को इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन शत–प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और इस मद में भारत के केन्द्रीय सरकार के द्वारा नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

2. राज्य रोजगार गारंटी कोष:–इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा।

3. मध्याह्न भोजन योजना (Mid Day Meal Scheme-MDMS)–यह योजना काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना में स्कूली बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन दिया जाता है। इसका भार भी केंद्र सरकार ही वहन करती है। इस योजना पर 2007-08 में लगभग 7324 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है। इसमें केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को ही सम्मिलित किया जाता है।

चित्र : 3.6

बिहार के एक स्कूल में अधिकारी की उपस्थिति में मध्याह्न-भोजन का बँटवारा बच्चों के बीच किया जा रहा है।

4. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम:– इस कार्यक्रय को सबसे पहले पाँचवीं पंचवर्षीय योजना सन् 1974-79 में देश से गरीबी निवारण हेतु लागू किया गया । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था–देश की गरीब जनता को कम से कम न्यूनतम जरूरतों जैसे–पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि की पूर्ति कराना था।

5. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम:– (Integrated Rural Development Programme (IRDP)) गरीबी निवारण के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 से देश के सभी प्रखंडों में लागू किया गया। यह एक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसमें गाँवों के गरीबों को उत्पादक परिसंपत्ति (Productive Assets) देकर उनकी आय में वृद्धि की

© BSTBPC Not to be Published

कोशिश की जाती है ताकि वे अतिरिक्त आय अर्जित कर गरीबी रेखा के ऊपर जा सकें।

6. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarn Jayanti Gram Rozgar Yojana (SGSY)) :- अप्रैल, 1999 में IRDP का नाम स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कर दिया गया। यह केंद्र सरकार द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में चालू रखा गया।

7. जवाहर रोजगार योजना (Jawahar Rozgar Yojana) :-यह एक मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को अप्रैल, 1989 में प्रारंभ किया गया था।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) को मिला दिया गया है। NREP को अक्टूबर, 1980 में सीमांत किसान, कृषि श्रमिक आदि को उनके बेकार समय में पूरक रोजगार-सृजन की दृष्टि से प्रारंभ किया गया तथा RLEGP को अगस्त 1983 में प्रारंभ किया गया था जिसके माध्यम से भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की बात कही गयी।

© BSTBPC Not to be Published

8. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (Prime Minister's Rozgar Yojana):- 1993-94 में यह योजना शहरी क्षेत्र में बेकार शिक्षित युवकों को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रारंभ की गई थी। 1994-95 में इसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी विस्तारित किया गया। 1999-2000 में इसके द्वारा करीब 2.20 लाख लोगों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, 2001 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ की संपूर्ण रोजगार योजना की घोषणा की।

9. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY):- इस योजना को 2000-01 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में गुणवत्ता के सुधार के लिए जैसे-स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा ग्रामीण सड़कों में सुधार के उद्देश्य से रखा गया है।

10. स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (Swarn Jayanti Shahari Rozgar Yojana or SJSRY) :- इस कार्यक्रम को दिसम्बर, 1997 से प्रारंभ किया गया है। यह योजना शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार तथा कम रोजगाररत लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई। 2004-05 में इस योजना के लिए 103 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

गैर-सरकारी प्रयास :

गरीबी के निदान के रूप में कुछ गैर-सरकारी प्रयास भी किए जा रहें हैं जो निम्नलिखित हैं:-

1. स्वरोजगार :-सरकारी प्रयास के अतिरिक्त गैर-सरकारी प्रयास भी गरीबी दूर करने के लिए गाँवों एवं शहरों के स्तर पर काफी कारगार सिद्ध हुआ है। इसके लिए गरीब व्यक्ति सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंक की सहायता से खुद रोजगार करना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए व्यक्ति स्वयं रोजगार को चुनता है और अपनी इच्छानुसार काम कर आय अर्जित करता है तथा धीरे-धीरे बैंक से लिए गए कर्ज को चुकता करता जाता है। कर्ज समाप्ति के बाद व्यक्ति का वह रोजगार अपना हो जाता है और वह व्यक्ति स्वावलम्बी हो जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति के रहन-सहन में आय बढ़ने के कारण बदलाव आ जाता है।

2. सामूहिक खेती :-

कृषि में छोटे-छोटे कठिनाइयों को आसानी से दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाने लगा। भारतीय कृषि में मूलत: कुछ विसंगतियाँ हैं जैसे—खेतों का विखंडन, खेतों पर मेड़ों का होना, सिंचाई के साधन का अभाव होना, फसलों की सुरक्षा का अभाव इत्यादि। इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए सामूहिक खेती का उद्‌गम हुआ। फलस्वरूप गरीब कृषक तथा गरीब मजदूर की खेती में लगायी जाने वाली पूँजी की सुरक्षा की गारंटी भी सामूहिक खेती की ही देन है। यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और लोग एक-दूसरे के दुख व हानि आपस में बाँटते हैं जिसके कारण किसी खास पर हानि का बोझ नहीं पड़ता है और गरीब से गरीब भी अपने इस प्रयास से जीवनशैली में बदलाव लाते हैं।

चित्र : 3.7

एक साथ कई महिलाएँ धान की रोपनी करती हुई।

इस चित्र 3.7 में यह स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि खेतों में एक साथ काफी महिलाएँ सामूहिक रूप से खेती कर रही हैं जो आपस में काम के अलावा अपने सुख-दुख को भी बाँटती हैं।

© BSTBPC Not to be Published

3. सामुदायिक विकास कार्यक्रमः–गाँव स्तर पर सामूहिक खेती के जैसा ही सामुदायिक विकास का **उद्‌गम** हुआ। इसके अन्तर्गत विकास के कार्यक्रम को लोग एक साथ मिलकर करते हैं और उससे प्राप्त मजदूरी व लाभ को बराबर-बराबर आपस में बाँटते हैं। नतीजा यह होता है कि प्रत्येक **वांछित व गरीब** लोगों को काम करने का एक साथ मौका मिलता है। इस प्रयास से इस समूह में लगे सारे लोगों की गरीबी, आय बढ़ने के कारण दूर हो जाती है।

4. स्वयं सहायता समूहः– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण महिला एवं ग्रामीण पुरुष को गाँव के स्तर पर ही जो काम मिलता है उसे बिना प्रशिक्षण के ही करते हैं। इसके अन्तर्गत पुरुष एवं महिला जो एक साथ काम करने के लिए इच्छुक होते हैं उन्हें बैंक के द्वारा समूह में कर्ज देकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक समूह में 15 से 20 लोग ही होते हैं एवं महिला तथा पुरुष का अलग-अलग समूह बनाया जाता है। समूह में एक सचिव तथा एक अध्यक्ष होते हैं और समूह के सभी सदस्यों का बैंक में खाता होता है। कर्ज वापसी की जवाबदेही समूह के सभी सदस्यों को बराबरी का होता है। समूह में जो भी आमदनी होती है उसे आपस में बराबर-बराबर बाँट दिया जाता है।

इस प्रकार अप्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं और अपनी गरीबी को दूर करने में सफल होते हैं।

© BSTBPC
Not to be Published

सारांशः

भारत में गरीबी आजादी के छः दशकों के बीत जाने के बावजूद भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। गरीबी की अवधारणा एक विस्तृत अवधारणा है। यह समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज का बहुत बड़ा हिस्सा न्यूनतम जीवन स्तर से भी वंचित रह जाता है। इसका प्रत्यक्ष संबंध जीवन–स्तर से है। दुनिया के गरीब देशों के समूह को **'तीसरी दुनिया** कहा जाता है। भारत सहित **'तीसरी दुनिया'** के देशों में व्यापक गरीबी विद्यमान है। इसके अंतर्गत गरीबी के दो विशिष्ट मामले दर्शाये गए हैं जो ग्रामीण एवं शहरी के रूप में दर्शाया गया है। ग्रामीण गरीबी एवं शहरी गरीबी को मापने के लिए गरीबी रेखा को आधार बनाया गया है। खासकर बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार 1.3 करोड़ जनसंख्या है जिसमें देश की कुल गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का 1/7 वाँ भाग गरीबी रेखा के नीचे रहता है। यहाँ की औसत उपलब्धियाँ काफी नीचे है। बिहार की जनसंख्या का 40 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे रहती है। बिहार में गरीबी का परिदृश्य काफी जटिल है। 80 प्रतिशत घरों के मालिक अशिक्षित हैं। बिहार राज्य का पशुधन भी निम्न कोटि का है। गरीबी और बेरोजगारी बिहार की अतीत से जुड़ गया है जिसके कारण इन दोनों समस्याओं से छुटकारा पाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। भारत व राज्य सरकार के स्तर पर इस समस्या के निवारण हेतु भी अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परन्तु इसकी उपलब्धियाँ अभी भी उतनी दिख नहीं पड़ती है जितना दिखना चाहिए। फिर भी सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयास निरंतर चलायी जा रही है। समय के अंतराल में इसकी उपलब्धि अवश्य दृष्टिगोचर होगी और गरीबी से छुटकारा आम जनता को मिल सकेगी।

© BSTBPC Not to be Published

अभ्यास :

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग, घ) लिखें।

1. बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से

(क) कम है (ख) बराबर है
(ग) अधिक है (घ) इनमें से कोई नहीं

2. बिहार में 1999- 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था

(क) 42.6 (ख) 44.3
(ग) 54.3 (घ) इनमें से कोई नहीं

3. भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है?

(क) आर्थिक विषमता (ख) औद्योगिक विकास
(ग) गरीबी (घ) औद्योगिक पिछड़ापन

4. गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है?

(क) पहला (ख) दूसरा
(ग) तीसरा (घ) चौथा

5. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है?

(क) उड़ीसा (ख) झारखंड
(ग) पं० बंगाल (घ) उत्तर प्रदेश

6. गरीबी रेखा के नीचे रहना

(क) अमीरी का द्योतक है (ख) गरीबी का सूचक है
(ग) खुशहाली का सूचक है (घ) इनमें से किसी का भी सूचक नहीं है।

7. शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है।

(क) 2400 कैलोरी (ख) 2100 कैलोरी
(ग) 2300 कैलोरी (घ) 2200 कैलोरी

© BSTBPC Not to be Published

8. निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं:-

(क) कृषि (ख) उद्योग

(ग) बाढ़ (घ) इनमें से कोई नहीं

9. MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रु०प्रतिमाह किया गया।

(क) 328 रु० (ख) 524 रु०

(ग) 454 रु० (घ) 354 रु०

10. SGSY योजना की शुरूआत कब की गयी ?

(क) 2000 ई० (ख) 1999 ई०

(ग) 2001 ई० (घ) 1998 ई०

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:-

(i) बिहार आर्थिक दृष्टि से एक......................राज्य है।

(ii) योजना काल में गरीबी की रेखा से नीचे आनेवाले लोगों की प्रतिशत में......................
..............हुई है।

(iii) भारत में शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या......................है।

(iv) जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें......................कहा जाता है।

(v) जब निम्नतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थता हो तो उसे................कहते हैं।

(vi) MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्रों में................रु० प्रतिमाह किया गया ।

(vii) 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में..........................करोड़ जनसंख्या गरीब है।

© BSTBPC Not to be Published

III. सही कथन को टिक (✓) तथा गलत कथन को क्रॉस (✗) करें।

(i) राज्य में आधारभूत संरचना की कमी गरीबी का एक प्रमुख कारण है।

(ii) ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए कृषि आधारित उद्योगों के विकास की आवश्यकता है।

(iii) जनसंख्या में वृद्धि देश की एक प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है।

(iv) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा दी गयी है।

(v) शहरी क्षेत्र के व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की अपेक्षा कम काम करते हैं।

(vi) ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता है।

IV. निम्न संक्षिप्त शब्दों को पूर्ण रूपेण लिखें:-

(क) NSSO
(ख) MPCE
(ग) SHG
(घ) SGSY
(ङ) JRY
(च) IRDP
(छ) MDMS
(ज) NREP
(झ) PMRY
(ञ) PMGY

V. लघु उत्तरीय प्रश्न :

(उत्तर 20 शब्दों में दें)

1. योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है?
2. गरीबी के दो विशिष्ट मामले की विवेचना करें।
3. गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं।
4. क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है?
5. किन-किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब हैं?
6. गरीबी के कारणों में जनसंख्या-वृद्धि की क्या भूमिका है?
7. भारत में गरीबी के किन्हीं चार प्रमुख कारण बताएँ।
8. गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को संक्षिप्त चर्चा करें।
9. भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर-सरकारी प्रयासों को बताएँ।
10. बिहार में ग्रामीण गरीबी की क्या स्थिति है?
11. बिहार में ग्रामीण गरीबी के चार प्रमुख कारणों को बताएँ।
12. बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए किन्हीं पाँच उपायों को बताएँ।

VI. दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न :

(उत्तर 100 शब्दों में दें)

1. भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इस परिभाषा के आधार पर भारत में गरीबी के विस्तार का क्या अनुमान लगाया जाता है?

© BSTBPC Not to be Published

2. भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या कीजिए।
3. भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए।
4. भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की कमियाँ बतायें।
5. बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण कौन-से हैं? इस समस्या के समाधान के लिए उपाय बतायें।

उत्तर

I. वस्तुनिष्ठ :

(1) ग (2) क (3) ख (4) ख (5) क
(6) ख (7) ख (8) ग (9) क (10) ख

II. रिक्त स्थान :

(1) पिछड़ा (2) कमी (3) अधिक (4) अमीर
(5) गरीब (6) 454 रु० (7) 17 करोड़

III. सही-गलत :

(1) सही (2) सही (3) गलत (4) सही (5) गलत (6) सही

© BSTBPC Not to be Published

परियोजना कार्य (Project Work) :

1. एक गरीब परिवार की कहानी लिखें।
2. विभिन्न प्रकार के गरीबी को चित्र द्वारा दिखाएँ।
3. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का अपने गाँव में मूल्यांकन करें।
4. ग्रामीण महिला के बीच गरीबी के प्रमुख कारणों को नुक्कड़ नाटक के द्वारा विद्यालय में प्रदर्शित करें।
5. अकाल एवं बाढ़ से उत्पन्न गरीबी के समय आपके गाँव में लोग कैसे जीविकोपार्जन करते हैं? उसका वर्णन करें।
6. वर्ग स्तर पर गरीबी संबंधित करें।
7. आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा प्रसारित होने वाली गरीबी पर एक कहानी लिखें।

संदर्भ :

- N.C.E.R.T. वर्ग IX अर्थशास्त्र
- भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास –श्रीमति उर्मिला शर्मा
- अर्थशास्त्र – डॉ० सुमन
- भारती भवन – वर्ग IX
- भारत का आर्थिक विकास – डॉ० दीपा श्री
- आर्थिक सर्वेक्षण – 2006-07
- भारत की 2001 जनगणना रिपोर्ट
- गरीबी और अकाल – डॉ० अमर्त्य सेन
- आर्थिक विकास और स्वातंत्र्य – डॉ० अमर्त्य सेन
- कुरुक्षेत्र–मासिक पत्रिका

© BSTBPC Not to be Published